Prabhat Khabar (Date: - 20/12/2019)

कुछ ऐसा होगा पटना का नया कलेक्ट्रेट भवन

पटना का नया कलेक्ट्रेट

बोधगया का कल्चरल सेंटर

लाइफ रिपोर्टर @ पटना

इंडियन रोड कांग्रेस के प्रदर्शनी में भवन निर्माण विभाग के स्टॉल पर प्रदेश में बनने वाले कई भव्य संरचनाओं के मॉडल दिखे. इनमें कुछ मॉडल को पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिसमें राजगीर में बन रहे विशाल स्टेडियम, पटना कलेक्ट्रेट का नया भवन, बोधगया का कल्चरल सेंटर और वैशाली का बुद्ध सम्यक दर्शन स्तूप शामिल है. राजगीर में बन रहे स्टेडियम कांप्लेक्स में 40 हजार की क्षमता वाले मुख्य क्रिकेट स्टेडियम के साथ दो फुटबाल के स्टेडियम भी शामिल होंगे, जिनमें एक प्रैक्टिस और एक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के लिए होगा. साथ ही इंडोर गेम के लिए चार स्टेडियम के साथ एडमिस्ट्रेटिव ब्लॉक और खिलाड़ियों के रहने के लिए कमरे भी बने होंगे. बोधगया का कल्चरल सेंटर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा हॉल होगा और इसमें 2000 दर्शकों के बैठने की क्षमता होगी. पटना कलेक्टेरिएट का नया भवन भी आर्किटेक्चर का एक सुंदर नमूना होगा, जो इसके मॉडल को देखने से ही स्पष्ट है. वैशाली के बुद्ध सम्यक दर्शन में महात्मा बुद्ध के अवशेष रखने की योजना है और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनने की संभावना को देखते हुए इसे भव्य रूप दिया गया है.

राजगीर स्टेडियम.

Prabhat Khabar (Date: - 20/12/2019)

नयी व्यवस्था • साइबर डीआइजी का होगा नया पद

जल्द तैयार होगा साइबर पुलिस का नया कैडर

कौशिक रंजन ▷ पटना

राज्य में साइबर अपराधों पर नकेल कसने, इनकी समुचित मॉनीटरिंग करने के साथ ही इसे लेकर व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए एक नया साइबर कैडर तैयार किया जा रहा है. इसके तहत पुलिस महकमे में पहली बार डीआइजी (साइबर) का पद बनाया किया गया है. इसके अलावा इससे संबंधित सभी स्तर के करीब 50 नये पद तैयार किये गये हैं. ये सभी पदाधिकारी यानी पूरा कैडर एडीजी (इओयू) के अंतर्गत काम करेंगे. इन्हीं के अंतर्गत राज्य में साइबर सेल का पूरी कार्यप्रणाली काम करती है. इन तमाम पदों पर कैबिनेट के स्तर पर अंतिम मुहर लगने के बाद इन पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी.

साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट बनाने वाला बिहार पहला राज्य

यह साइबर कैडर पहले से मौजूद साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट के साथ मिलकर काम करेगा. बिहार देश में पहला राज्य है, जहां सभी जिलों में एक या इससे ज्यादा संख्या में साइबर क्राइम और सोशल मीडिया यूनिट का गठन कर दिया गया है. मौजूदा समय में ऐसी यूनिट की संख्या 74 है. प्रत्येक में 10 लोगों की टीम है, जिसमें छह पुलिसकर्मी और चार टेक्निकल पदाधिकारी मौजूद हैं.

1 पुलिस महकमे ने तैयार कर लिया इससे संबंधित प्रस्ताव, कैबिनेट से मुहर लगने के बाद होगा यह लागू

2 इस साइबर कैडर में तीन एसपी, छह डीएसपी, छह इंस्पेक्टर, छह दारोगा और 30 सिपाही होंगे शामिल

इतनी संख्या में होंगे ये नये पदाधिकारी

इस कैडर के लिए डीआइजी से लेकर सिपाही तक के नये पदों का सृजन किया गया है. इसमें डीआइजी के एक पद के अलावा तीन पद एसपी होगा. इसमें एक एसपी (अनुसंधान), एसपी (जागरूकता एवं ट्रेनिंग) और एसपी (पोर्टल एवं समन्वय) का पद होगा. इसके अलावा छह डीएसपी, छह इंस्पेक्टर, छह दारोगा और 30 सिपाही के पद होंगे. इन सभी पदों पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बहाली की जायेगी. यह पूरा कैडर राज्य की आर्थिक अपराध इकाइ (इओयू) में मौजूद राज्य साइबर सेल या कंट्रोल सेंटर से जुड़कर काम करेगा.

ये होंगे इसके प्रमुख कार्य

मौजूदा समय में राज्य में सभी स्तर के साइबर क्राइम से जुड़े मामले करीब 700 आते हैं. इन मामलों का निबटारा करने या इसमें हर तरह से संबंधित थानों को मदद देने के लिए यह साइबर यूनिट खासतौर से काम करेगी. इसके अलावा पेंडिंग या लंबित पड़े मामलों में व्यापक अनुसंधान की जिम्मेदारी भी इस पर होगी. इनके साथ तकनीकी स्तर पर काम को मदद करने और किसी साइबर अपराधी के बारे में जानकारी मिलने पर उसकी तुरंत गिरफ्तारी या छापेमारी करने के लिए पूरी टीम इनकी अपनी होगी.

Hindustan (Date: - 20/12/2019)

बेंगलुरु सहित कई शहरों की तर्ज पर बंद नालों की सफाई को होगा प्रयोग

बिहार में रोबोट करेंगे अब नालों की सफाई

18 सौ लोग सीवर सफाई में जान गंवा चुके हैं

बेंगलुरु, मुंबई, केरल इंदौर में अभी रोबोट से हो रही नालों की सफाई

अच्छी खबर

पटना | हिन्दुस्तान ब्यूरो

राज्य में आने वाले दिनों में नालों की सफाई रोबोट करेंगे। यह व्यवस्था राजधानी पटना समेत सभी शहरों के पुराने बंद नालों के लिए होगी। देश के कई प्रमुख शहरों में यह प्रयोग शुरू किया गया है। अब बिहार में भी इसे अमल में लाने की तैयारी है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने संबंधित कंपनी को प्रेजेंटेशन के लिए आमंत्रित किया है।

देश में बेंगलुरु, मुंबई, केरल सहित कई निकायों में बंद और बड़े नालों की सफाई रोबोट की मदद से की जा रही है। वहीं दिल्ली भी रोबोट के जरिए नाला सफाई के विकल्प पर विचार कर रहा है। अब बिहार ने भी इस प्रयोग को अपनाने का निर्णय लिया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा बीते दिनों बेंगलुरु गए थे। वहां उन्होंने रोबोट की मदद से नाला सफाई को देखा। उन्होंने वहां के अधिकारियों से भी इस संबंध में जानकारी हासिल की। अब उस कंपनी को बिहार आने के लिए आमंत्रित किया गया है। इस व्यवस्था के तहत रोबोट को नाले में उतार दिया जाता है। पाइप के जरिए वह गंदगी को खींच लेता है।

नई व्यवस्था

- नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रेजेंटेशन के लिए कंपनी को आमंत्रित किया
- रोबोट के जरिए नाला सफाई से जानमाल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी

हुआ था जलजमाव

दरअसल पटना में ही बोरिंग कैनाल रोड, नाला रोड, आशियाना सहित कई बड़े नाले हैं, जो बंद हैं। हाल ही में पटना में अभूतपूर्व जलजमाव हुआ था। जलनिकासी नहीं होने के कारण पानी घरों में घुस गया था। नाला उड़ाही ठीक ढंग से नहीं हो पाने के चलते यह हालात बने थे।

नहीं होगी कोई क्षति

रोबोट के जरिए नाला सफाई से जानमाल की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सकेगी। न्यायालय के अलावा राष्ट्रीय सफाई आयोग सहित विभिन्न मानवाधिकार संगठन सीवर और बंद नालों की सफाई मजदूरों के जरिए न कराने की बात कहते रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक बीते पांच वर्षों में नाला और सीवर सफाई के दौरान करीब 1870 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

राज्य के बंद नालों की सफाई अब रोबोट से कराई जाएगी। प्रेजेंटेशन के लिए कंपनियों को बुलाया गया है। उसके बाद तय किया जाएगा कि कितने रोबोट की जरूरत होगी।

– **सुरेश कुमार शर्मा**, मंत्री, नगर विकास एवं आवास

Prabhat Khabar (Date: - 20/12/2019)

छोटे पर्यटन स्थल होंगे विकसित मंदिरों में होगी ठहरने की व्यवस्था

संवाददाता ▸ पटना

बिहार में देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पर्यटन विभाग ने रोड मैप तैयार किया है. इसके तहत छोटे पर्यटन स्थलों को विकसित किया जायेगा. मंदिर परिसरों में ठहरने की व्यवस्था की जायेगी. पर्यटन स्थलों को इंटरनेट से जोड़ा जायेगा. देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों की आनलाइन बुकिंग हो सकेगी. पर्यटकों की सुरक्षा और व्यवस्था को और बेहतर किया जायेगा. आंकड़ों को देखें, तो पर्यटकों की संख्या बिहार में काफी बढ़ी है. इसमें विदेशी पर्यटकों की संख्या में 7.1 प्रतिशत से काफी अधिक बढ़ोतरी हुई है.राज्य सरकार ने विभाग का बजट बढ़ाकर 91.02 करोड़ से अधिक कर दिया है. रोड मैप को कैबिनेट में बहुत जल्द स्वीकृति के लिए भेजा जायेगा. स्वीकृति मिलने के बाद मार्च, 2020 से यह लागू हो जायेगा.

विभाग ने सभी डीएम से मांगी थी रिपोर्ट : विभाग इको टूरिज्म को बढ़ावा देने और पर्यटकों को राज्य की संस्कृति और पौराणिक कथाओं से परिचित कराने के लिए अलग से तैयारी कर रहा है. विभाग ने विभिन्न जिलों के डीएम से सहयोग मांगा था कि उनके जिले में कहां-कहां ऐसे स्थान हैं, जिन्हें पर्यटकों के लिए विकसित किया जा सकता है.

नयी सुविधाएं

- बिहार में पर्यटकों के लिए हर सुविधा ऑनलाइन की जायेगी, जिसकी शुरुआत कई जगहों पर हो चुकी है. राज्य भर में टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग, गेस्ट हाउस या खाने के लिए ऑर्डर ऑनलाइन कर पायेंगे.
- **धार्मिक और पर्यटन स्थलों तक पहुंचने में परेशानी नहीं हो, इसको लेकर भी तेजी से काम हो रहा है.**
- सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी पर्यटन स्थलों पर पुलिस चौकी व सीसी टीवी कैमरा रहेगा.

मेंटेनेंस पॉलिसी से होगा विकास

पर्यटन विभाग पहली बार मेंटेनेंस पॉलिसी बना रहा है. इस पॉलिसी के तहत अब मंदिर परिसर में गेस्ट हाउस बनाया जायेगा. बिहार के प्रसिद्ध स्थलों पर भीड़ होने के बाद भी पर्यटकों को सुविधा नहीं दी जाती है, लेकिन पॉलिसी तैयार होने के बाद छोटी-बड़ी सभी जगहों पर पर्यटकों को रहने में परेशानी नहीं होगी. जिस गेस्ट हाउस में रहने की सुविधा विभाग के माध्यम से होगी, उस जगह का मेंटेनेंस पॉलिसी के तहत होगा.